विज़न इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में 22 जून 2018 को नई दिल्ली में आयोजित पॉलिसी बूटकैम्प–2018 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीया लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

.....

- Vision India Foundation के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर अपने विचार साझा करना मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। आप सब भारत के सुनहरे भविष्य के कार्यवाहक हैं, निर्माता हैं, चिंतक हैं।
- राष्ट्रनिर्माण के लिए देशभक्ति, दृढ़संकल्प, नई योजना, नई सोच एवं असीम ऊर्जा लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले एवं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले सभी युवाओं एवं कई प्रख्यात कंपनियों एवं संस्थानों में सेवा देने वाले professionals का इस विशेष कैम्प में जुड़ना एक सुखद संयोग रहा।
- मैं विज़न इंडिया फाउंडेशन के आयोजकों को भी बधाई देती हूं जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम की आधारशिला रखी जो गर्वनेंस एवं पब्लिक पॉलिसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को इन प्रतिभागियों को अवगत कराता है। विविध विषयों के सुविख्यात चिंतकों, विचारकों एवं विशेषज्ञों से सीधे संवाद का मंच उपलब्ध कराने के लिए Vision India Foundation बधाई के पात्र है।
- 21 दिनों की इस कार्यशाला में न केवल कई brainstorming sessions हुए बल्कि प्रतिभागियों के लिए योग/मेडिटेशन की refreshing classes भी हुए। इनके नियमित अभ्यास से प्रतिभागियों की मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर में वृद्धि हुई होगी।

BULLET POINTS

Life of an MP

- MPs को काफी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी accountability बहुत ज्यादा है क्योंकि अब पब्लिक ज्यादा जागरूक एवं सचेत है।
- प्रत्येक पांच साल में चुनाव होते हैं और उन्हें अपने आपको सिद्ध करना पड़ता है।
- पार्टी के अंदर भी उन्हें बहुत सारे stiff competition face करने होते हैं।
- Politicians के बारे में public perception बहुत सकारात्मक नहीं है। ऐसा क्यों?
- जनप्रतिनिधियों को 24 घंटे आम जनता के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। बाकी प्रोफेशनल्स की तुलना में Remuneration कम और जिम्मेदारी ज्यादा है।
- उनके ऊपर delivery के लिए जनता, पार्टी, पार्लियामेंट, फैमिली सबका दबाव रहता है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों से miracles की उम्मीद करती है।
- Social Media के कारण जनता का दबाव संसद व जनप्रतिनिधियों पर बढ़ा है।
- उदाहरण के तौर पर अगर फसल का दाम बढ़ता है तो consumers government को complain करते हैं और घटता है तो किसान complain करते हैं।
- युवा वर्ग की बहुत सारी आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं हैं। वे तेजी से विकास चाहते हैं। सरकार ने उनकी उम्मीदों के मुताबिक विकास कार्यों को गति दी है एवं नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया है।
- जनप्रतिनिधिगण लोगों के जीवन को प्रभावित एवं प्रेरित करते हैं। जैसे कि–

1. इंदौर स्वच्छता सर्वे में लगातार दो वर्षों से नम्बर 1 आया है। (जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की भूमिका)
2. धर्मस्थलों की सफाई एवं स्वच्छता के लिए स्वप्रेरणा से लोगों का आगे आना दर्शाता है कि यदि लोगों को सही दिशा की ओर प्रेरित किया जाए तो सार्वजनिक कार्यों एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में स्वप्रेरणा से जुड़ते हैं और ऐसे कार्यों के स्थायी एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

3. कुओं, बावड़ियों, तालाबों की सफाई एवं गहरीकरण, साथ ही उन मिट्टी का उपयोग खेतों में किया गया है।
4. लोगों ने मिलकर कम्यूनिटी फॉरेस्ट की दिशा में काम किया है।
5. Indore से Rail Connectivity- आज इंदौर चार मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा एकमात्र ऐसा शहर है जो देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी से सीधे रेल सम्पर्क से जुड़ा है।

- Parliament में Presiding Officer का मुख्य कार्य है सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के बीच संतुलन बनाते हुए संसद का कार्य सुचारू रूप से संचालित करना। यह बहुत ही delicate and balancing act है।
- लोगों का perception है कि पार्लियामेंट में व्यवधान ज्यादा होता है काम कम। लेकिन वास्तविकता यह है कि मेम्बर्स Questions के माध्यम से सरकार को accountable बनाते हैं और सरकार भी उनके प्रश्नों का विस्तृत जवाब देती है जोकि parliament में lay होता है। पार्लियामेंट कमेटी सिस्टम, जो Mini Parliament है, निरंतर काम करती रहती है जिसमें debate, discussion, oversight of government's programmes and performance का आकलन होता रहता है।
- Parliament ensures accountability of Executive- Question Hour, Zero Hour, Adjournment Motion, Calling Attention Motion, Parliamentary Committees etc.
- सरकार का फोकस है Minimum Government, Maximum Governance. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि जैसी कई योजनाओं ने देश के सभी नागरिकों के लिए आशा जगाने का काम किया है।
- परिवर्तन के कुछ उदाहरण आपको बता रही हूं। झाबुआ में ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी चुनने जंगल जाना पड़ता था। उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस चुल्हा एवं सिलिंडर उपलब्ध कराने से उनके जीवन में सुरक्षा तो आई

है, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है क्योंकि अब उन्हें धुआं नहीं सहना पड़ता है।

- उसी प्रकार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइडलाइन्स के तहत जम्मू और कश्मीर में गांवों में सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा था। Parliment की Rural Development Committe के दौरे के दौरान इस बात पर ध्यान गया एवं उसके बाद उस गाइडलाइन में संशोधन हुआ। अब कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काफी सड़कों का निर्माण हुआ है। यह कमेटी सिस्टम के recommendation से ही संभव हो पाया है।
- इसी प्रकार संसद ने कई उत्कृष्ट कानून बनाए हैं जिन्होंने आम नागरिक के जीवन में व्यापक बदलाव लाए हैं जैसे–

1. Right to Information Act 2005,
2. Right to Education Act, 2009,
3. Anti Defection Law, 2003,
4. Maternity Benefit Act, 2017,
5. Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act, 2017,
6. Real Estate Regulatory Authority Act, 2016 and
7. Food Security Act, 2013.

- For ease of governance, Govt. has repealed around 1200 outdated and irrelevant laws.
- संसद सदस्यों को वर्तमान परिवेश में विविध विषयों की विशद जानकारी देने ताकि संसद में चर्चा का स्तर उच्च हो सके और policy formulation को तर्कसंगत, समसामयिक एवं प्रासंगिक बनाया जा सके, मैंने पार्लियामेंट में Speaker Research Initiative की स्थापना की है। SRI information dissemination का एक माध्यम है। इसी क्रम में SRI एक महीना और तीन महीना का internship के साथ–साथ युवा विद्यार्थियों के लिए फेलोशिप भी प्रारंभ किया है ताकि वे संसद के practice and procedure,

legislation process को बारीकी से समझ सकें। A North-Eastern Chapter has been set-up at Guwahati.

- SRI internship अब विदेशी युवाओं के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे उन देशों के साथ people-to-people contact एवं संबंधित देशों के बीच कूटनीतिक संबंध (diplomatic relationship) और सुदृढ़ होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Sustainable Development Goals (SDG) के तहत 17 targets, 169 Goals निर्धारित किए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरा करना है। हमनें भी पार्लियामेंट में इस पर चर्चा के लिए हर सेशन में exclusively एक दिन रखा है।
- हम पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षा के साथ–साथ समय की बचत होती है। साथ ही, हमने MPs और स्टॉफ के लिए विभिन्न Parliamentary Procedures को डिजिटलाइज्ड कर दिया है।
- "Empowered women can empower Nation" की थीम पर 2015 में एक National Women's Legislators Conference आयोजित किया गया था।
- इसी वर्ष ''We for Development'' की थीम पर National Legislators Conference आयोजित किया गया जिसमें देश भर के जनप्रतिनिधिगण ने हिस्सा लिया एवं सार्थक एवं लाभकारी चर्चाएं हुईं।
- पार्लियामेंट की working को समझने के लिए media के लोगों के लिए Workshop का आयोजन समय–समय पर किया जा रहा है।
- Parliament House Complex में Energy conservation के लिए 120 किलोवाट के सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी क्षमता को increase किया जा रहा है। पूरे संसद भवन कॉम्पलेक्स में LED lightings provision किया गया है एवं ई–रिक्शा भी प्रचलन में आ गई है।

- Session में पार्लियामेंट एवं पार्लियामेंट proceedings देखने आने वाले visitors की संख्या भी बढ़ी है। पिछले बजट सत्र में 22974 लोग संसद देखने आए।

———————